

आवासीय विद्यालय में साक्षात्कार हेतु पात्रता एवं दिशा/निर्देश

क्र.सं.	पद नाम	पात्रता
1	व्याख्याता	सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि मय बी.एड. तथा राजस्थान शिक्षा सेवा के कार्मिक जिन्हें स्कूल व्याख्याता पद पर न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव हो।
2	वरि.अध्यापक ग्रेड-1A	स्नातक उपाधि मय बी.एड. तथा राजस्थान शिक्षा सेवा के कार्मिक जिन्हें द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पद पर न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव हो।
3	अध्यापक लेवल-2	सम्बन्धित विषय में स्नातक उपाधि मय बी.एड. तथा राजस्थान अधिनस्थ शिक्षा सेवा के कार्मिक जिन्हें स्कूल में अध्यापक लेवल-2 पद पर न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव हो।

दिशा-निर्देश:-

- केवल वे ही कार्मिक आवेदन करें जो वर्तमान में शिक्षा विभाग में राज्य सेवा में सेवारत हैं। कार्मिक केवल एक ही स्थान से आवेदन करे अन्यथा आवेदन निरस्त माना जायेगा।
- वेबसाईट पर बताए गए रिक्त पद अनुमानित हैं तथा उनमें कमी या वृद्धि संभावित है।
- विशेष योग्यताधारी कार्मिकों को अनुभव में छूट दिये जाने एवं अन्य समस्त अधिकार निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा सचिव राईस के पास सुरक्षित हैं।
- कार्मिक अपनी योग्यता, अनुभव एवं किये गये विशिष्ट कार्यों से संबंधित प्रमाण-पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रति सलंगन करे।
- कार्मिक की आयु विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि तक 55 वर्ष से अधिक न हो।
- प्रतिनियुक्ति पर चयनित कार्मिकों को मूल वेतन का 15 प्रतिशत विशेष वेतन भत्ता एवं निःशुल्क आवास सुविधा देय होगी है।
- प्रतिनियुक्ति पर चयनित कार्मिकों को विद्यालय परिसर में बने आवासों में ही रहना होगा।
- बालिका विद्यालयों में समस्त पद महिला कार्मिकों द्वारा भरे जावेंगे। महिला कार्मिक के उपलब्ध न होने की स्थिति में ही पुरुष कार्मिक के चयन पर विचार किया जावेगा।
- चयन से पूर्व अथवा पश्चात् कोई भी सूचना गलत पाये जाने पर राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
- प्रारम्भ में प्रतिनियुक्ति 2 वर्ष के लिए होगी। तदोपरान्त सेवायें संतोषप्रद पाये जाने पर प्रतिनियुक्ति आगे बढ़ाई जा सकती है।
- प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी की सेवाएं संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर उन्हें कार्यमुक्त किया जा सकता है।
- ऐसे कार्मिक जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है/विचाराधीन है या जिनके सेवा अभिलेख में विपरीत टिप्पणियां अंकित हैं, वे कार्मिक आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
- समस्त मामलों में किसी वाद के होते हुए अन्तिम निर्णय का अधिकार निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं प्रदेन सचिव, राईस को होगा।
- राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित जिलों में कार्यरत कार्मिकों को, नियमानुसार प्रतिबन्धित जिलों में ही प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है।